Vol 6 Issue 2 March 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal
International Recognized Multidisciplinary Research Journal
ISSN: 2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 2 | March - 2016

सामाजिक परिवर्तन में आरक्षण की भूमिका

अशोक कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महिला महाविद्यालय, हर्रैया, बस्ती (उ.प्र.)।

प्रास्ताविक

जिस प्रकार समग्र सृष्टि में समय के साथ परिवर्तन होता है उसी प्रकार मानव समाज भी परिवर्तनशील है। समाज में आदिकाल से ही नित्य नये प्रयोजनों के द्वारा एक के बाद एक परिवर्तन संस्कृति, प्रथाओं, अर्थनीति एवं शासन व्यवस्था में होते रहे हैं। एक व्यवस्था लगातार बनी नहीं रह सकती इसलिए कालान्तर में एक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का उदय होता है। सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार का क्रमिक परिवर्तन अन्त में विकास एवं उन्नयन के रूप में परिलक्षित होता है। परन्तु कोई भी सामाजिक परिवर्तन तभी न्यायोचित एवं विकास के रूप में वर्णित किया जा सकता है जब यह निम्नतर अवस्था में पड़े लोगों के जीवन में सुखद बदलाव लाने में सक्षम होता है। ''इस हिसाब से भारत में उत्कृष्ट सामाजिक परिवर्तन उस परिवर्तन को ही कहा जा सकता है जो यहां की परम्परागत आर्थिक वितरण व्यवस्था में बहुसंख्यक आबादी को राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका उचित हिस्सा मुहैया करा सके। दूसरे शब्दों में एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन जो कि मुख्यधारा से अलग–थलग पड़े लोगों को मुख्यधारा में ला सके, ही सच्चा सामाजिक परिवर्तन कहलायेगा।''[1]

सामाजिक परिवर्तन की उपर्युक्त विशेषता के आधार पर भारतीय समाज का आकलन करने पर स्पष्ट होता है कि मानव विकास के इतिहास में भारतीय समाज एक ऐसा समाज रहा है जिसमें परिवर्तन लगभग नगण्य मात्र हुआ है। भारतीय समाज में परिवर्तन की इस निश्चलता को देखकर ही महान् समाज विज्ञानी कार्ल मार्क्स ने लिखा है– ''भारत के अतीत का राजनीतिक स्वरूप जितना भी परिवर्तनशील क्यों न रहा हो, सुदूर पुराकाल से लेकर वर्तमान तक इसके सामाजिक रूप में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया है, एकदम अपरिवर्तित रह गया है। इस समाज की आर्थिक संरचना को कोई भी परिवर्तन बदल नहीं पाया है। परिणामस्वरूप दूसरे देशों के प्राचीन व मध्ययुग के राजा,

बैरन्स, गिल्ड, मास्टर, दास इत्यादि का समाज में आज कोई अस्तित्व नहीं है। यह सब परिभाषाएं श्रेणी समाज वाले देशों में अर्थहीन एवं अतीत का इतिहास मात्र रह गयी हैं, भारतीय समाज के प्रागैतिहासिक ब्राह्मण, शूद्रादि आज भी वही आदिम माहात्मय लिए स्वमहिमा विद्यमान एवं सम्पूर्ण शक्ति से क्रियाशील हैं।''

''आज के भारतीय महानगरों की चकाचौंध, आठ से बारह लेन तक बनी शानदार सड़कें, उपभोक्तावादी वस्तुओं का अंधाधुंध प्रयोग देखकर किसी को भी यह भ्रम हो सकता है कि मार्क्स की उपयुर्क्त टिप्पणी आज के भारत के सन्दर्भ में लागू नहीं होती है। परन्तु सच्चाई यह है कि सुदूर अतीत की तरह आज भी सवर्णों का देश की सम्पदा–संस्थाओं पर एकाधिकार विद्यमान है, बहुसंख्यक मूलनिवासी आज भी शिक्षाहीन, भूमिहीन एवं व्यवसायहीन हैं।''[2]

मार्क्स ने राजा, बैरन्स और ब्राह्मण, शूद्रादि की तुलना करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों में जो टिप्पणी की है उसे बिना किसी तर्क के सामाजिक परिवर्तन के इतिहास का सार कहा जा सकता है। उन्होंने जिन राजा, बैरन्स, गिल्डमास्टर, दास इत्यादि की चर्चा की है वे स्तरीभूत मानव समूहों की श्रेणियां थीं जबकि ब्राह्मण–शूद्र आदि विश्व के एकमात्र जाति और वर्ण पर आधारित मानव समूह हैं। श्रेणी समाजों की सर्वप्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें केवल गरीब एवं अमीर में विभाजित मानव समूहों की श्रेणियां रहीं और गरीब और अमीर की दो श्रेणियों में विभाजित मानव समूह अपने कर्मों के कारण गरीब से अमीर और अमीर से गरीब में परिवर्तित होते रहे। इस प्रकार विकास के क्रम में परिवर्तनशील श्रेणी समाजों के राजा, बैरन्स, नाइट्स, दास, भूमिदास इत्यादि विलुप्त होकर आधुनिक काल में प्रधानतः अमीर और गरीब की श्रेणी में रह गये हैं।

श्रेणी समाज के मानव समूहों के विपरीत ब्राह्मण, शूद्रादि समूहों पर आधारित ''वर्ण व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो मूलतः सम्पदा, संसाधनों, पेशों और मर्यादा की वितरण व्यवस्था है।''[3]

इस व्यवस्था को आर्य मनीषियों द्वारा प्रवर्तित किया गया तथा स्वयं के लाभ के लिए दैवीय कृत्य के रूप में प्रचारित किया गया। ''वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के लिए पेशे निर्दिष्ट कर दिये गये। ब्राह्मणों के लिए अध्यापन, पौरोहित्य, राज्य संचालन में सलाह, क्षत्रियों के लिए शासन–प्रशासन, सैन्यवृत्ति, भूस्वामित्व तथा वैश्यों के लिए पशुपालन, व्यवसाय, वाणिज्य आदि कर्म निर्दिष्ट किये गये। शूद्रों के लिए ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना निर्दिष्ट किया गया। पर इस सेवा के बदले में उन्हें पारिश्रमिक मांगने का अधिकार नहीं था। परन्तु कर्म शुद्धता की अनिवार्यता और एक वर्ण समूह द्वारा दूसरे वर्ण समूह के कर्म को अपनाने की मनाही के कारण सभी वर्गों के लोग अपने पेशे तक ही सीमित रह गये। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था ने एक एक आरक्षण–व्यवस्था का रूप ले लिया जिसे हिन्दू आरक्षण भी कहा जा सकता है।''[4]

''ईश्वरकृत धार्मिक व्यवस्था में जब पेशों में विचलनशीलता को निषिद्ध कर इसे हिन्दू आरक्षण व्यवस्था के रूप में विकसित कर दिया गया तब मूलनिवासी शूद्राति–शूद्र की स्थिति बद से बदतर होती चली गयी। इसी के परिणामस्वरूप विगत साढ़े तीन हजार वर्षों से बौद्धकाल को छोड़कर इन मूलनिवासियों के लिए शिक्षक, पुरोहित, भू–स्वामी, सैनिक, राजा, व्यवसायी इत्यादि बनने के सारे रास्ते बन्द रहे।''[5]

''इन शिक्षाहीन, भूमिहीन, व्यवसायहीन लोगों के जीवन में आर्थिक बदलाव के रास्ते में हिन्दू आरक्षण एवरेस्ट की भांति खड़ा रहा रहा। मानव सभ्यता के विशाल काल खण्ड में समग्र विश्व में जितने लोगों को साम्राज्यवादी शक्तियों के कारण वंचित एवं अमानवीयता का शिकार बनना पड़ा है, वह संख्या अकेले भारत के मूलनिवासी शूद्रों के समक्ष छोटी पड़ जायेगी।''[6]

''सामाजिक परिवर्तन का जो दरवाजा क्षत्रियों की तलवारों के साये में संरक्षित तथा धर्मशास्त्र के कानूनों द्वारा बन्द रहा उसे बौद्धोत्तर काल में पहली बार तोड़ने का साहसिक कार्य लार्ड मैकाले के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने किया। उन्होंने आई0पी0सी0 (इण्डियन पैनल कोड) द्वारा न केवल कानून की नजरों में ब्राह्मण–अब्राह्मण सबको एक बराबर किया बल्कि हिन्दू आरक्षण के वंचितों को भू–स्वामित्व व शिक्षार्जन का अधिकार प्रदान करने के साथ ही उन सभी पेशों को अपनाने का अधिकार दे दिया जो मात्र हिन्दू साम्राज्यवाद के आरक्षण प्राप्त वर्ग के लिए आरक्षित थे।''[7]

परन्तु सदियों के हिन्दू आरक्षण व्यवस्था द्वारा शोषण के कारण शूद्रातिशूद्र इस कदर अयोग्य एवं अपंग हो चुके थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त अवसर का लाभ उठाने में भी असमर्थ सिद्ध हो गये।

''सर्वप्रथम महात्मा फुले ने हिन्दू आरक्षण को सामाजिक परिवर्तन की बाधा तथा शूद्रातिशूद्रों की दुर्दशा का मूल कारण समझकर उसके प्रतिकार के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को जन्म देने का मन बनाया। उन्होंने कांटे से कांटा निकालने की जो परिकल्पना की वही आरक्षण रूपी औजार के रूप में 1873 में ''गुलामगीरी'' के पन्नों से निकलकर जनता के बीच आयी।''[8]

फुले ने 'कम्युनिस्ट घोषणा पत्र' के भारतीय संस्करण 'गुलामगीरी' में लिखा, ''हमारी दयालु सरकार को भट्ट ब्राह्मणों को उनकी संख्यानुसार सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है। किन्तु उसके साथ ही अन्य छोटी जातियों के लोगों की भी उनकी जनसंख्या अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए। इससे सभी भट्ट ब्राह्मण सरकारी नौकरों के लिए एकसाथ मिलकर हमारे अज्ञानी शुद्रों को नुकसान पहुंचाना सम्भव न होगा।''[9]

''गुलामगीरी की ये पंक्तियां ही परवर्ती समय में भारत में सामाजिक न्याय का मूलमंत्र बनीं। इन्हीं पंक्तियों को पकड़कर शाहूजी महाराज ने 26 जुलाई, 1902 को शूद्रातिशूद्रों के लिए पहली बार आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय की शुरूआत की तो पेरियार ने 27 दिसम्बर, 1929 को मद्रास प्रान्त में बड़े पैमाने पर दलित–पिछड़ों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिलाया।''[10]

ज्योतिबा फुले ने हिन्दू आरक्षण की काट के लिए जिस औजार का आविष्कार किया वह सबसे प्रभावी रूप में तब सामने आया जब डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा इसके इस्तेमाल का व्यापक अवसर सुलभ कराया। ''वास्तव में अगर मुख्य धारा से अलग–थलग पड़े लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना ही सच्चा सामाजिक परिवर्तन के रूप में विशेषित हो सकता है तो आंबेडकरी आरक्षण ही उसके लिए प्रभावी औजार साबित हुआ। अगर जहर की काट जहर से हो सकती है तो अमानवीय व परिवर्तनरोधी हिन्दू आरक्षण की काट आम्बेडकरी आरक्षण ही है।''[11]

संविधान में डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के लिए आरक्षण सुलभ कराने के साथ अनुच्छेद 340 का जो प्रावधान रखा उससे परवर्तीकाल में मंडलवादी आरक्षण की शुरूआत हुई जिससे पिछड़ी जातियों की बेहतरी का रास्ता साफ हुआ।[12]

संविधान के द्वारा डॉ0 अम्बेडकर ने आरक्षण के माध्यम से वर्ण–व्यवस्था नामक आर्थिक वितरण व्यवस्था के वंचित मूलनिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने का जो उपक्रम चलाया वह विश्व की एकमात्र घटना नहीं है। आरक्षण पर गहन शोध करने वाले डॉ. राम समुझ ने लिखा है, ''मूल निवासियों का शोषण और दमन, विशेषकर महिलाओं का, एक वैश्विक परिघटना रही है।'' संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड जैसे विकसित देशों में शोषण और भेदभाव का तरीका भारत से भिन्न रहा है। बीसवीं शदी की शुरूआत में शिक्षा के प्रसार के चलते शोषित समूहों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति आयी और पूरी दुनिया में नागरिक अधिकार आंदोलनों की शुरूआत हुई। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पतन और संसदीय व्यवस्था के विश्वमय सूत्रपात के साथ 'समानता' की एक नई अवधारणा का प्रसार हुआ। नस्ल, रंग, धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव व दमन एक सामाजिक बुराई के रूप में चिन्हित हुआ। ऐसे में प्रायः सभी देश भेदभाव के उन्मूलन व वंचित वर्गों सहित महिलाओं के विकास के लिए तरह–तरह के कानून बनाने की दिशा में अग्रसर हुए।

''भारत में 'रिजर्वेशन पॉलिसी' और अमेरिका का अफरमेटिव ऐक्शन प्रोगाम (Affirmative Action Programme-AAP) समाज के वंचित समूहों के विकास के हित में किये गये प्रयास की बेहतरीन मिसाले हैं। ब्रिटिश सरकार ने भेदभाव के उन्मूलन और नागरिकों के मध्य 'समान अवसर' को बढ़ावा देने के लिए 'सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट' और 'रेस रिलेसन्स ऐक्ट' पारित किया। इसी तरह आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने देश के मूलनिवासियों की उन्नति के लिए विशेष कानून एवं विकास मूलक कार्य सूची बनाया।''[13]

भारत में आम्बेडकरी आरक्षण से महज सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया ही शुरू हुई, इसके द्वारा मुकम्मल परिवर्तन नहीं हो सकता था। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया मुकम्मल हो जाती यदि सरकारी क्षेत्र की नौकरियों, संसद व विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के साथ ही राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू आरक्षण के वंचितों को उनका हिस्सा मिल जाता।''[14] परन्तु आम्बेडकरी आरक्षण के छोटे से सरकारी क्षेत्र में ही लागू होने के कारण ऐसा संभव न हो पाया। ''जबकि दूसरे देशों में विभिन्न प्रकार की सार्थक हस्तक्षेप की अलग–अलग नीतियां शुरूआती दिनों से ही सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में लागू हैं।''[15]

''दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत के मूल निवासियों की बेहतरी की दिशा में लागू आरक्षण का दायरा तो सीमित रहा ही, ऊपर से एक और त्रासदी यह रही कि यहाँ के शासक व बुद्धिजीवी वर्ग में आरक्षण को लागू करवाने का उत्साह बहुत ही कम रहा।''[16]

अमेरिका में जब 2 मार्च, 1968 को प्रकाशित कर्नर आयोग की सिफारिशों के आधार पर अमेरिकी दलितों को अमेरिका की पूंजी, सरकारी व गैर–सरकारी क्षेत्र की नौकरियों, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण संस्थाओं, मीडिया, फिल्म, टी.वी. इत्यादि में भागीदार बनाने का राष्ट्र के समक्ष आह्वान किया गया तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए शान्ति को ध्यान में रखकर वहाँ के प्रभुसत्ता प्राप्त वर्ग ने तहेदिल से उसका स्वागत किया। परवर्तीकाल में डायवर्सिटी लागू करना अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य मानते हुए अमेरिकी गोरे समाज ने अफरमेटिव ऐक्शन प्रोग्राम (Affirmative Action Programme-AAP) द्वारा राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वंचितों की भागीदारी देने का जो सिलसिला शुरू किया, उसके परिणाम आश्चर्यजनक रहे।[17]

इसके विपरीत भारत में जिन लोगों ने सदियों से भारत के मूल निवासियों को नर–पशु बनाकर उनका शोषण किया वे उदार न बन सके तथा अपनी क्षमता का अधिकाधिक उपयोग, मेरिट का बहाना व तरह–तरह के कानूनी अड़ंगे लगाकर, आरक्षित वर्ग को अवसरों से वंचित करने में करते रहे।

चन्द्रभान प्रसाद और उनके कुछ साथियों के सौजन्य से भारतीय बौद्धिक क्षितिज पर डायवर्सिटी का उदय हुआ।18 बाद में इनके प्रयास और और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सक्रिय सहयोग से 12–13 जनवरी, 2002 को भोपाल कांफ्रेन्स में इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निबटने व सामाजिक परिवर्तन की धारा को तीव्रतर करने के उद्देश्य से 21 सुत्रीय दलित एजेंडा जारी हुआा जिसे 'भोपाल घोषणापत्र' भी कहते हैं। भोपाल घोषणापत्र पर देश भर से आये विशिष्ट दलित बुद्धिजीवियों ने अपने समर्थन की मोहर लगाया था। कई हजार वर्ष पूर्व वैदिक मनीषियों ने वर्ण–व्यवस्था के सूत्रों द्वारा शूद्रातिशूद्रों को वितरणहीनता की खाई में धकेलने का जो जघन्य अपराध किया था उसी का मुकम्मल प्रतिकार था 'भोपाल घोषणापत्र'।[19]

भोपाल घोषणापत्र के 21 सूत्रीय एजेण्डे में अस्पृश्य–आदिवासियों के लिए जंगल–जमीन पर अधिकार, आसानी से हथियार व वित्तीय सुविधाएं सहज सुलभ कराने की मांग तो की ही गयी थी, परन्तु उसका केन्द्रीय तत्व 'डायवर्सिटी' नीति थी जो कि अमेरिका के 'अफरमेटिव ऐक्शन' का रूपांतरित रूप थी जिसके तहत अमेरिका के दलितों को सरकारी/गैर–सरकारी नौकरियों, वस्तुओं की सप्लाई, तैयार उत्पादों के डीलरशिप, ठेकों, फिल्म, टी0वी0, प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, ज्ञान के केन्दों इत्यादि में भागीदारी दी जा रही है। भोपाल घोषणा के 21 सूत्रीय एजेण्डे में शामिल डायवर्सिटी की प्रभावकारिता से प्रभावित होकर तत्कालीन राष्ट्रपति के0आर0 नारायणन ने 25 जनवरी, 2002 की शाम राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में 'भोपाल घोषणा' को अपनाने की अपील राष्ट्र के समक्ष कर डाली। इससे प्रेरित होकर बंगलौर में 19–20 अप्रैल, 2003 को 'बंगलौर पहल' जारी हुआ जिसमें निम्न मांगे उठीं–

1. सरकार अपने प्रयोजन के लिए की जाने वाली खरीददारी, भवन और सड़क निर्माण के ठेकों सहित शराब की दुकानों के लिए की जाने वाली लाइसेन्स व सरकारी डीलरशिप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दस्तकार पिछड़ी जातियों के लिए अनिवार्य रूप से सप्लायर/कांट्रैक्ट डायवर्सिटी लागू करे,
2. सभी औद्योगिक कम्पनियां जो सरकारी संस्थाओं से ऋण लेती हैं तथा राज्य प्रदत्त सुविधाओं का उपभोग करती हैं, अपनी संस्थाओं में अवश्य ही सप्लायर/डीलरशिप/रिक्रूटमेंट डायवर्सिटी लागू करें,
3. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया रिक्रूटमेंट डायवर्सिटी एवं फिल्म एवं संगीत उद्योग अनिवार्य रूप से अमेरिका की तरह डायवर्सिटी लागू करें,
4. निजी क्षेत्र के स्कूल, कालेज भी एडमिशन और रिक्रूटमेन्ट डायवर्सिटी लागू करें,

भोपाल घोषणा का असर सम्भवतः राजग सरकार द्वारा गठित संविधान समीक्षा आयोग पर भी पड़ा। इसलिए आयोग ने अपनी

संस्तुतियों में सरकारी दुकानों, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी और सरकारी ठेकों में पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण देने की बात कर डाली है।

21वीं सदी में मूल निवासियों को भूमण्डलीकरण की आंधी से बचाने में सक्षम डायवर्सिटी के लिए आने वाले दिनों में विराटतम आंदोलन संगठित होने जा रहा है।[20]

भोपाल घोषणा जारी होने के कुछ अन्तराल के मध्य ही डायवर्सिटी लागू करने के लिए संसद में आवाज गूंजने के साथ ही कई शहरों में 'डायवर्सिटी ऐक्शन कमेटियां' गठित की गयी हैं। माननीय आर. के. चौधरी के बी.एस. 4 पार्टी तथा उदितराज की जस्टिस पार्टी डायवर्सिटी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए अभियान चलाने हेतु देश के विभिन्न अंचलों में लोग संगठित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में उदारीकरण, निजीकरण के चलते आरक्षण के खात्मे की आशंका से जो ढेरों संगठन व कई राजनीतिक पार्टियां निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए आंदोलन चला रही हैं उन्हें भी डायवर्सिटी आंदोलन से जुड़ना ही है। ऐसे लोगों को जिस दिन पता चल जायेगा कि डायवर्सिटी के मांग के समक्ष निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लिलीपुट जैसी है,[21] वे डायवर्सिटी आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए अवश्य ही बाध्य होंगे।

सामाजिक परिवर्तन को तीव्रतर करने में सक्षम डायवर्सिटी आंदोलन सही दिशा में गतिमान है। इस संदर्भ में डायवर्सिटी आंदोलनकारी श्री राम समुझ की पुस्तक – Reservation Policy : Its Relevance in Modern India, पढ़कर आश्वस्त हो सकते हैं। यह पुस्तक लेखक का विधि विषयक शोध ग्रंथ है जिसमें भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड इत्यादि देशों के उन कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन है जिसे विभिन्न देशों में रंग, धर्म, जाति और लिंग आधार पर वंचना का शिकार हुई आबादी के हित में प्रवर्तित किया गया है।

वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाजों में जो भी विकास परिलक्षित हो रहा है वह सेवा क्षेत्र और विधायिका में आरक्षण के फलस्वरूप ही है। परन्तु आरक्षण की परम्परागत आम्बेडकरी नीति आज के उदारीकरण, भूमण्डलीकरण के दौर में पुरानी पड़कर अपनी प्रासांगिकता खो चुकी है। विगत 15 वर्षों में सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में तेजी से गिरावट आयी है। अतः नई वैश्विक अर्थनीति के अनुरूप आरक्षण नीति की समीक्षा और इसके ढांचे के आधुनिकीकरण की जरूरत है। आरक्षित वर्ग के लोग परम्परागत आरक्षण पर पूरी तरह निर्भर हो गये हैं।[22] जबकि व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग, प्रोफेशन इत्यादि कई क्षेत्र हैं जो इनके स्पर्श से बाहर हैं। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया जैसे नये क्षेत्रों में इनकी भागीदारी प्रायः शून्य है।[23] अतः आवश्यकता इस बात की है कि परम्परागत आम्बेडकरी आरक्षण को बनाये रखने के लिए दबाव बनाने के बजाय हम डायवर्सिटी लागू करने के लिए दबाव बनायें।

अफरमेटिव ऐक्शन प्रोगाम द्वारा अमेरिका में साकार किये जा रहे 'डायवर्सिटी' सिद्धान्त के भारतीय बौद्धिक क्षितिज पर लगातार विस्तार के कारण कुछ लोग इस अभियान को हतोत्साहित करने के लिए यह दुष्प्रचार चलाते रहे हैं कि यह उस अमेरिकी राज्य का आइडिया है जहाँ नस्लभेद कायम है। जबकि डायवर्सिटी समर्थक यह स्पष्ट करते हैं कि डायवर्सिटी की जड़ें ठीक उसी तरह अम्बेडकरवाद में निहित हैं जैसे विश्व के अन्यान्य देशों में विकसित बुद्धिज्म की जड़ें भारत में हैं। डॉ. राम समुझ इसकी जड़ों को अम्बेडकरवाद से जोड़ते हुए लिखते हैं, ''अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाये जिसका अनुसरण करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1950 के दौर में 'सिविल राइट्स मूवमेंट' के नाम से आंदोलन चलाया। सिविल राइट्स मूवमेंट के परिणामस्वरूप अमेरिकी सरकार ने भारत के आरक्षण नीति के पैटर्न पर अफरमेटिव ऐक्शन प्रोगाम शुरू किया।''[24] विभिन्न देशों के आरक्षण प्रणालियों का गहन अध्ययन करने वाले मार्क ग्लान्टर अनुसार, ''अमेरिकी सरकार ने अफरमेटिव ऐक्शन प्रोगाम ; ।च्द्ध का विचार भारत की आरक्षण नीति से उधार लिया है।''[25] परन्तु जैसा कि वस्तुस्थिति है उधार लेने वाला इस सन्दर्भ में उधार देने वाले से बेहतर परिणाम देने में सफल हो गया है।

अमेरिका के अफरमेटिव ऐक्शन प्रोगाम ने अमेरिकी दलितों के आर्थिक विकास में अपनी सफलता को प्रमाणित कर दिया है, जबकि भारत की आरक्षण नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक विकास का कोई प्रावधान नहीं है। परम्परागत आरक्षण प्रणाली से व्यक्ति विशेष तो लाभान्वित हो सकता है पर पूरा समुदाय नहीं। ऐसे में अफरमेटिव ऐक्शन प्रोगाम से कुछ अच्छी बातें उधार लेकर आरक्षण पद्धति को और उपयोगी व प्रभावशाली बनाया जा सकता है।[26] डायवर्सिटी समर्थक अपना आंदोलन इसीलिए चला रहे हैं ताकि भारत की आरक्षण प्रणाली का विकसित रूप डायवर्सिटी लागू करवा कर वर्ण व्यवस्था के सदियों के वंचित मानव समूहों का आर्थिक उत्थान और आम्बेडकरवाद का विस्तार किया जा सके।

सन्दर्भ–

1. एच.एल. दुसाध, सामाजिक परिवर्तन और बी.एस.पी., पृष्ठ–13
2. एच.एल. दुसाध, डायवर्सिटी : दलित सशक्तीकरण का सर्वोत्तम औजार, पृष्ठ–9
3. एच.एल. दुसाध, वर्ण व्यवस्था : एक वितरण व्यवस्था, पृष्ठ–213
4. एच.एल. दुसाध, हिन्दू आरक्षण और बहुजन का संघर्ष, पृष्ठ–257
5. एच.एल. दुसाध, सामाजिक परिवर्तन और बी.एस.पी., पृष्ठ–382
6. एच.एल. दुसाध, सामाजिक परिवर्तन और बी.एस.पी., पृष्ठ–15
7. एच.एल. दुसाध, सामाजिक परिवर्तन में बाधक हिन्दुत्व, पृष्ठ–601
8. एच.एल. दुसाध, डायवर्सिटी : दलित सशक्तीकरण का सर्वोत्तम औजार, पृष्ठ–13
9. शरद यादव, महात्मा फुले : साहित्य और विचार, पृष्ठ–227
10. एच.एल. दुसाध, सामाजिक परिवर्तन और बी.एस.पी., पृष्ठ–228
11. एच.एल. दुसाध, डायवर्सिटी : दलित सशक्तीकरण का सर्वोत्तम औजार, पृष्ठ–13
12. एच.एल. दुसाध, सामाजिक परिवर्तन और बी.एस.पी., पृष्ठ–229
13. डॉ. राम समुझ, रिजर्वेशन पॉलिसी : इट्स रिलेवेन्स इन मॉडर्न इण्डिया, पृष्ठ–197

14. डॉ. सुखदेव थोराट, निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति, पृष्ठ–19
15. एक्शन एड 2004, अनटचेबिलिटी इन रूरल इण्डिया, एक्शन एड दिल्ली
16. डॉ0 अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङमय, खण्ड–1, पृष्ठ–95
17. एच.एल. दुसाध, डायवर्सिटी : दलित सशक्तीकरण का सर्वोत्तम औजार, पृष्ठ–671
18. वही पृष्ठ–14 से 15
19. वही पृष्ठ–74
20. एच.एल. दुसाध, डायवर्सिटी : दलित सशक्तीकरण का सर्वोत्तम औजार, पृष्ठ–202
21. एच.एल. दुसाध, मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं : डायवर्सिटी (राम विलास पासवान से एक संवाद), पृष्ठ–19
22. डॉ. राम समुझ, रिजर्वेशन पॉलिसी : इट्स रिलेवेन्स इन मॉडर्न इण्डिया, पृष्ठ–34
23. वही पृष्ठ–34
24. वही पृष्ठ–14
25. वही पृष्ठ–391
26. वही पृष्ठ–391

अशोक कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महिला महाविद्यालय, हर्रैया, बस्ती (उ.प्र.)।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org